भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3561

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटे को कम करना

3561. **एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, जो आयात में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि, विशेष रूप से सोने और पेट्रोलियम के अधिक आयात के कारण अक्तूबर में बढ़कर 27.14 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया;

(ख) क्या सरकार सोने के आयात को विनियमित करने और कम करने के लिए आगे कार्रवाई करने का विचार रखती है जिसमें सितंबर 2024 में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई;

(ग) यदि हां, तो भारत के व्यापार संतुलन पर सोने के आयात के प्रभाव को किस तरह से प्रबंधित किया जाएगा; और

(घ) गैर-पेट्रोलियम निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास को जारी रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जो 211.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): अक्टूबर 2024 में व्यापार घाटा (पण्यवस्तु + सेवाएँ) में 9.90 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 15.85 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो अक्टूबर 2024 में 37.5 प्रतिशत का सुधार है। अक्टूबर 2024 में पण्यवस्तु व्यापार घाटे में भी अक्टूबर 2023 में 30.43 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में सुधार होकर 11.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 26.99 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा, अक्टूबर 2024 के दौरान सोने का आयात 7.12 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 7.23 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें 1.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(ख) और (ग): सोने का आयात सितंबर 2023 में 4.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा बढ़कर सितंबर 2024 में 4.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, अक्टूबर 2024 में सोने का आयात अक्टूबर 2023 में 7.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटकर 7.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें 1.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(घ): निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। कुछ उपायों में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना, ट्रेड कनेक्ट ई-पोर्टल, जनसुनवाई जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाना और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और व्यापार ब्लॉकों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत करना शामिल है। विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी और समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करना। विभाग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सक्षम इन्वॉयरन्मेंट बनाने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिलों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत और जुड़ाव कर रहा है। इसके अलावा, नई विदेश व्यापार नीति (2023) भारत को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने और इसे एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने के लिए एक खाका तैयार करती है। इससे भारत के व्यापार निष्पादन और प्रतिस्पर्धात्मकता में और सुधार होगा।

*****